





कमल/सिखार/... 13-10-17 के साथ प्राप्त  
नीला रिपोर्ट का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि आराजी  
खसरा नम्बर 158 रकबा 0.14 हैक्टययर गै.मु.रास्ता है। भू  
अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह भी  
अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 84 में प्रार्थी ने पक्का  
आवास बना रखा है। उक्त आराजी तथा गै.मु. रास्ता के मध्य  
ख. नं. 86 स्थित जिसमें प्रार्थी स्वयं सहखातेदार है। इस रिपोर्ट  
से यह तथ्य सामने आता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी  
खसरा नम्बर 84 में मकान बने हुये हैं जहां पर प्रार्थी निवास  
करता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए का  
मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी काश्तकार को उनकी  
खातेदारी की जोत तक पहुंचने के लिये रास्ता का अन्य कोई  
विकल्प नहीं हो तो अन्य खातेदारों की कृषि भूमि में से कीमतन  
रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है किन्तु यहां पर यह स्थिति  
नहीं है। प्रार्थी की आराजी खसरा 84 कृषि उपयोग में नहीं आ  
रही है। इसके अलावा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के मद संख्या  
4 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 86  
में मौजूद रास्ते का उपयोग उपभोग करता रहे। इस प्रकार प्रार्थी  
के पास रास्ता उपलब्ध है तथा आराजी खसरा नम्बर 86 में  
प्रार्थी स्वयं भी सह-खातेदार है। इसलिये इस प्रकरण पर  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान  
लागू नहीं होते हैं। इसलिये प्रकरण में प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध

उपस्यण्ड अधिकारी  
नहवा (जि.स.स.)

# न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज पप्पूराम बनामनाम साहबसिंह वगैरा मु. सं.
-------------	--


करवाने या आराजी खसरा नम्बर 86 में स्थित रास्ता की भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश नहीं दिये जा सकते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

### आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30-09-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
महया (जिल्ला दैला)